वकालत या राजनीति

सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई टालने और यहां तक कि उसे अगले आम चुनाव के बाद सुने जाने की दलील देने वाले वकील एवं कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल अगर चौतरफा आलोचना से दो-चार हैं तो इसके लिए वह अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकते। जब दोनों पक्ष और साथ ही एक तरह से सारा देश यह चाह रहा है कि इस मामले का निपटारा जितनी जल्दी हो जाए तो बेहतर तब उसे ठंडे बस्ते में डालने वाली दलीलों का कोई मतलब नहीं। भले ही कपिल सिब्बल ने केवल वकील की हैसियत से अपनी दलील दी हो, लेकिन उनका रवैया संकीर्ण राजनीति से भी ग्रस्त दिख रहा और देश की भावनाओं के विपरीत भी। आखिर वह इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए कि अयोध्या मसले का जल्द निपटारा ठीक नहीं? क्या यह अजीब नहीं कि वह एक ओर तो संकीर्ण राजनीतिक कारणों से अयोध्या मामले की सुनवाई जुलाई 2019 तक टलवाना चाहते हैं और दूसरी ओर यह सवाल भी कर रहे हैं कि इस मसले पर राजनीति क्यों हो रही है? बेहतर होगा कि वह इस बात को समझें कि राजनीति करने का अवसर खुद उन्होंने उपलब्ध कराया है। वह सुप्रीम कोर्ट में वकील की हैसियत से वकालत भर कर रहे थे या फिर राजनेता की हैसियत से यह हिसाब भी लगा रहे थे कि आम चुनाव के बाद इस मसले का निपटारा हो तो कांग्रेस के लिए अच्छा रहेगा? निःसंदेह नेता के साथ-साथ एक वकील होने के नाते वह किसी भी मामले की वकालत कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा करते समय वह अदालत में नेता की तरह आचरण करेंगे तो फिर सवाल उठेंगे ही। इस पर हैरत नहीं कि उनके कारण कांग्रेस को जवाब देने में मुश्किल पेश आ रही है। कांग्रेस यह कहकर नहीं बच सकती कि वकील होने के नाते कपिल सिब्बल कोई भी केस लड़ें उससे मतलब नहीं, क्योंकि एक समय उसके एक और वकील नेता जब केरल के लॉटरी संचालकों का केस लड़ रहे थे तो पार्टी ने उन्हें इसके लिए बाध्य किया था कि वह यह केस छोड़ें।

अयोध्या मामले में कपिल सिब्बल की भूमिका पर इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य हाजी महबूब भी इससे सहमत नहीं कि अयोध्या मसले की सुनवाई 2019 में होनी चाहिए। भले ही बाद में हाजी महबूब कपिल सिब्बल के रवैये पर अपनी आपत्ति वापस लेते नजर आए हों, लेकिन यह एक तथ्य है कि वह भी यही चाहते हैं कि इस मसले का निपटारा जल्द हो। सदियों पुराने अयोध्या मामले के निपटारे में और देरी हो, इस पर तो उसी की दिलचस्पी हो सकती है जो इस प्रकरण के बहाने राजनीतिक रोटियां सेंकते रहना चाहता हो। आखिर यह क्या पहेली है कि कांग्रेस एक ओर तो यह आरोप लगाती है कि भाजपा अयोध्या मसले के बहाने राजनीति करना चाहती है और दूसरी ओर उसके एक वकील नेता यह नहीं चाह रहे कि इस प्रकरण का जल्द पटाक्षेप हो? अगर इस मामले का अदालत से जल्द निपटारा हो जाए तो फिर भाजपा या अन्य किसी के लिए राजनीति करने की गुंजाइश ही क्यों बचेगी?

भ्रष्टाचार से लड़ाई

डिजिटल इंडिया की मुहिम को जारी रखते हुए राज्य में अब भवनों-भूखंडों की रजिस्ट्री सुविधा भी ऑनलाइन हो गई है। मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था का शुभारंभ कर दिया है। प्रेरणा-3 के नाम से वेबसाइट बनायी गई है। इस योजना की शुरुआत वैसे तो अक्टूबर में ही हो गई थी जब दो भिन्न चरणों में 40 जिलों के 194 उपनिबंधक कार्यालयों को ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ा गया। बाकी बचे नौ मंडल, 35 जिले और 160 उपनिबंधक कार्यालयों में पांच दिसंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध हो गई। सरकारी कार्यालयों की तरह रजिस्ट्री आफिस में भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आम हैं। बगैर दलालों के रजिस्ट्री कराना टेढ़ी खीर है। अव्यवस्था के शिकार लोग अब राहत की सांस ले सकते हैं।

> शासन को लगातार इस सुविधा की मॉनीटरिंग करानी होगी और समय-समय पर आने वाली दिक्कतों को दूर कर इस सेवा का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करना होगा

ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू हो जाने से लोगों का समय और पैसा तो बचेगा ही, भवनों या भूखंडों की रजिस्ट्री और पारदर्शी हो जाएगी। भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने वालों को स्टांप शुल्क, रजिस्ट्री की तारीख और समय की जानकारी भी मिल सकेगी। तय समय पर वे जमीन और मकान का क्रय-विक्रय और खारिज-दाखिल आदि करा सकेंगे। अक्सर देखा जाता है कि मैनुअल सिस्टम से एक संपत्ति की कई-कई बार रजिस्ट्रियां हो जाती हैं। ऑनलाइन व्यवस्था में अगर कोई एक ही संपत्ति की दो बार रजिस्ट्री कराता है तो निश्चय ही पकड़ा जाएगा। भ्रष्टाचार को दूर करने की दिशा में यह एक सार्थक प्रयास है। शासन को लगातार इसकी मॉनीटरिंग करानी होगी और समय-समय पर आने वाली दिक्कतों को दूर कर इस सेवा का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करना होगा। जनता को इसके फायदों से परिचित कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है तभी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की उसकी कोशिशें रंग लाएंगी।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या आपको लगता है कि सरकारें प्रदूषण की समस्या को लेकर गंभीर नहीं हैं?

आज का सवाल

क्या अयोध्या विवाद की सुनवाई को टालने की वकील कपिल सिब्बल की दलील राजनीति से प्रेरित थी?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम एसएमएस से प्राप्त नतीजों के साथ जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

मजहब की तरह नहीं है धर्म

उदय प्रकाश अरोड़ा

जो कुछ निश्चित चीजों को नहीं मानते, मजहब उन्हें अपने से अलग मानता है। धर्म अलग करने में नहीं, बल्कि सबको जोड़ने में विश्वास करता है

इन दिनों भिन्न-भिन्न कारणों से धर्म और धार्मिकता के साथ मजहब, संस्कृति आदि को लेकर खूब चर्चा हो रही है। यह पहली बार नहीं है। आजादी के बाद जब तमाम देसी रियासतों को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण हुआ तब भी इन सब विषयों पर खूब चर्चा हो रही थी। दुनिया के तमाम मुल्कों को इस पर हैरानी थी कि भाषाओं, बोलियों, संप्रदायों, जातियों, खानपान, रहन-सहन और अनेक भौगोलिक विभिन्नताओं के बावजूद भारतवासी एकता स्थापित कर कैसे एक राष्ट्र बन गए? तब कुछ पश्चिमी पर्यवेक्षकों ने तो यहां तक आशंका जाहिर की थी कि यह एकता अधिक समय तक कायम नहीं रहेगी और यह संघ 14-15 वर्षों में छिन्न-भिन्न हो जाएगा। वास्तव में इतनी विषमताओं के साथ राष्ट्रीय एकता की स्थापना का कोई अन्य ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। चीन ने अवश्य अपना एकीकरण कर भारत से भी बड़ा देश बना लिया, किंतु वहां एकरूपता अधिक होने और विभिन्नता कम होने से एकीकरण अपेक्षाकृत आसान रहा। फिर भारत में जो कुछ हुआ वह लोकतांत्रिक ढांचे के दायरे में हुआ जो कम बड़ी बात नहीं। भारत से इतर देखें तो पड़ोसी पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा उससे अलग हो गया। बांग्लादेश निर्माण के बाद भी बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और सिंध अपनी आजादी के लिए आवाज उठाते रहते हैं। वहीं भाषा, मजहब, खानपान, रहन-सहन की समानता होते हुए भी पश्चिम एशिया अनेक छोटे-छोटे मुस्लिम राष्ट्रों में बंटा है और हमेशा उनके बीच मारकाट जारी रहती है। पूरी दुनिया को एकता और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले यूरोप के लिए भी भारत की एकता ईर्ष्या का विषय बनी रही। ईसाई बहुल यूरोप में तमाम समानताएं हैं, लेकिन वहां ईसाईयत भी उन्हें जोड़ने में नाकाम रही। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तो यूरोप का नक्शा ही बदल गया। फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, पोलैंड, हंगरी, लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया जैसे नए राष्ट्रों ने जन्म लिया।

मुल्कों का टूटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी नहीं रुका। इजरायल के जन्म ने फलस्तीन के लिए समस्या पैदा कर दी। 1989-92 के बीच यूगोस्लाविया के सात टुकड़े हो गए। 1991 तक सोवियत संघ भी 15 राष्ट्रों में विभाजित हो गया। रूस का हिस्सा चेचन्या आजादी के लिए अब भी संघर्ष कर रहा है। वहीं स्पेन में भी कैटालोनिया खुद को आजाद देश बनाने की मुहिम में जुटा है। एकीकरण के इस विमर्श में सांस्कृतिक बहुलता यानी संस्कृतियों के संगम का मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो गया है। यह अब भारत ही नहीं पश्चिमी देशों में भी देखने को मिलता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा जैसे विकसित और समृद्ध देशों में काम की तलाश में आए लोगों और शरणार्थियों के बसने के कारण सांस्कृतिक बहुलता आई है। उनके लिए यह नया अनुभव कुछ समस्याएं भी पैदा कर रहा है, लेकिन भारत के लिए यह नया नहीं है और यहां हजारों वर्षों से विद्यमान है। विभिन्न संस्कृतियों के बीच रहकर कैसे मेल मिलाप के साथ रहा जा सकता है, यह कोई भारत से सीखे।

अवधेश राजपूत

बहुसंस्कृतिवाद के साथ भारत ने जो एकता वैदिक युग से बनाए रखी है उसका प्रमुख कारण है कि इस देश की संस्कृति की प्रमुख धारा ने सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया है। भारतीय जिस धर्म को मानते है उसका संबंध नैतिक मूल्यों और आचरण से है। उनका धर्म, मजहब की तरह नहीं है। मजहब को मानने वाले लोग कुछ निश्चित चीजों पर विश्वास करते हैं। यह एक ईश्वर, उसके विशेष दूत, पैगंबर और विशेष पुस्तक हो सकती है। जो इन निश्चित चीजों को नहीं मानता, मजहब उन्हें अपने से अलग मानता है। धर्म अलग करने में नहीं, बल्कि सबको जोड़ने में विश्वास करता है। यही वजह है कि प्रबुद्ध मुस्लिम यह मानने लगे हैं कि मुस्लिम समाज को भारत में चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि देश की बहुसंख्यक हिंदू जनता हमेशा से सहिष्णु और उदार रही है।

कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत, विशाल एवं श्रेष्ठ संस्कृत साहित्य, बदरीनाथ से लेकर रामेश्वरम जैसे तीर्थ और गंगा, यमुना से लेकर गोदावरी और कावेरी जैसी तमाम नदियों को पवित्र माना जाता है। ये सभी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसने भारत की एकता और परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखा है। मेगस्थनीज और ह्वेसांग जैसे विदेशी यात्रियों को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही भारत दिखाई पड़ा था।

भारत को जोड़ने में जिस धर्म और संस्कृति की भूमिका रही उसका साहित्य संस्कृत भाषा में है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, चरक और सुश्रुत का चिकित्सा विज्ञान, गणित, नक्षत्र विद्या आदि अधिकांश संस्कृत में है। भारत की एकता को मजबूत बनाने में जिन विद्वानों का उल्लेख किया जाता है उनमें कश्मीर के पंडित सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। घाटी के बाहर शरणार्थी के रूप में जो आज कश्मीरी पंडित हैं वे उन्हीं पाणिनी, पतंजलि, चरक, कालिदास, कल्हण, बिल्हण, अभिनव गुप्त, क्षेमेंद्र, मम्मटाचार्य, आनंदवर्धन और वामनाचार्य की संतान हैं जिन्होंने कश्मीर में रहकर ही संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया। कल्हण द्वारा लिखे ग्रंथ राजतरंगिणी को भारत में इतिहास का सर्वप्रथम ग्रंथ माना जाता है। कहा जाता है कि संस्कृत विद्वानों की भाषा रही है। यह आम जनता की बोलचाल में प्रचलित नहीं थी। इस विषय में कश्मीर अपवाद रहा है। ग्रियर्सन के अनुसार लगभग दो हजार वर्षों तक कश्मीर में संस्कृत आम जनता की बोलचाल की भाषा थी। आठवीं से पंद्रहवीं शताब्दी के बीच कश्मीर के 13-14 विद्वानों ने जितना लिखा वह संपूर्ण संस्कृत साहित्य के आधे भाग से भी अधिक है। अलंकारशास्त्र, नाट्यशास्त्र, कृषि शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, वास्तु विज्ञान और नक्षत्र विज्ञान के विकास में कश्मीरी विद्वानों का योगदान भारत में सबसे अधिक बढ़-चढ़कर था। भारत आने पर पश्चिमी विद्वानों ने संस्कृत अध्ययन के लिए जिन विद्वानों की सहायता ली उनमें कश्मीर के गोविंद कौल, नित्यानंद शास्त्री, मुकुंद राम शास्त्री, प्रो. जगधर, पं. दामोदर, सहज भट्ट और आनंद कौल प्रमुख थे।

पश्चिमी विद्वानों का यह संपर्क प्रमुख रूप से 1875 और 1940 के बीच विद्यमान था। कश्मीर में विकसित शैव धर्म आठवीं से 12वीं शताब्दी तक भारत का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक और धार्मिक आंदोलन था। कश्मीर में विकसित सूफी मत ने भी हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई पाटकर भारत की एकता को और अधिक सुदृढ़ बनाया है। कश्मीर की सूफी परंपरा, इस्लाम, शैव भक्ति आंदोलन ओर वेदांत का मिश्रण है। हिंदू और बौद्ध विचारधारा का भी सूफियों पर प्रभाव पड़ा। हिंदू धर्म के प्रभाव में ही सूफियों की एक नई धारा ने भारत में जन्म लिया जिसे 'ऋषि' शृंखला के नाम से जाना जाता है। शैव धर्म, सूफियों की ऋषि शृंखला तथा संस्कृत ज्ञान ने मिलकर कश्मीर में जिस कश्मीरियत को जन्म दिया है उसके अस्तित्व के बिना हिंदू संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। आजादी के समय जब भारत में दंगे हो रहे थे तब महात्मा गांधी को आशा की किरण केवल कश्मीर में दिखाई पड़ी। कुछ कश्मीरियों की हत्या होने के बावजूद घाटी में पूर्ण शांति रही। यह कश्मीर की उदारवादी परंपरा का फल था। अब वह परंपरा कहां गई?

(लेखक जेएनयू में ग्रीक चेयर प्रोफेसर रहे हैं)

response@jagran.com

उपचार के नाम पर अनैतिक व्यापार

एनके सिंह

इलाज में लापरवाही के मामले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य तंत्र को कठघरे में खड़े करने के साथ ही शर्मिंदा करने वाले हैं

दिल्ली स्थित एक नामी अस्पताल में एक महिला के जुड़वां बच्चे पैदा हुए-एक बेटा और दूसरी बेटी। डॉक्टरों ने बताया कि एक बच्चा मरा पैदा हुआ और दूसरा कुछ ही क्षण बाद मर गया। जब दुखी मां-बाप अपने सगे संबंधियों के साथ उन 'शवों' को अंतिम क्रिया के लिए ले जा रहे थे तो आधे रास्ते में पिता ने देखा कि एक 'शव' में कुछ हरकत हो रही है। फौरन उसे कफन से निकाल कर पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां कई दिनों तक चले इलाज के बाद उसे बचाया नहीं सका। दरअसल घंटों पॉलिथीन में ऑक्सीजन के अभाव में बंद बच्चे की स्थिति गंभीर हो गई थी। मीडिया में खबर आने के बाद देश के स्वास्थ्य मंत्री ने मामले का संज्ञान लिया। इसके पहले गुरुग्राम में एक अन्य नामी गिरामी अस्पताल ने सात साल की एक बच्ची के 15 दिन चले असफल इलाज में पिता को 16 लाख रुपये का बिल पकड़ा दिया था। सोशल मीडिया और बाद में मुख्यधारा की मीडिया में खबर आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने मामले का संज्ञान लिया। तीसरे मामले में नोएडा के एक मशहूर अस्पताल में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी तीन दिन पहले मर चुकी थी, पर अस्पताल प्रबंधन ने वेंटीलेटर पर रख कर तीन दिनों में हजारों रुपये का बिल बनाया। पता नहीं स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस मसले का संज्ञान लिया या नहीं?

उक्त तीनों घटनाएं पिछले 15 दिन के भीतर घटी हैं। दिल्ली-एनसीआर में उपचार में लापरवाही के ये तीन मामले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य तंत्र को कठघरे में खड़े करने के साथ ही शर्मिंदा करने वाले हैं। इन तीन घटनाओं से तीन निष्कर्ष निकलते हैं। आप या आपका बच्चा बीमार पड़े तो निजी क्षेत्र के बड़े अस्पताल में जाने के बाद तीन बातों का ध्यान रखें। अस्पताल में जरूरी नहीं कि इलाज हो और अगर हो तो मरीज बच ही जाए। फिर कब मरे और कब मरना बताया जाए, यह भी अस्पताल और डॉक्टर की 'प्रोफेशनल बुद्धिमत्ता' पर निर्भर करेगा। अगर मरना बता भी दिया गया तो जरूरी नहीं कि यह सच हो इसलिए उसे एक बार किसी और डॉक्टर से दिखा लें। और आखिर में अगर दुर्भाग्य से मरीज मर भी गया हो तो आप उस बिल के सदमे से न मरें। एक सीख यह भी है कि अगर आप अस्पताल और उसके मनमाने बिल से बच भी गए तो कम से कम सोशल मीडिया की शरण अवश्य लें। कई बार मुख्यधारा का मीडिया तभी मामले की गंभीरता समझता है जब वह सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है। आखिर क्या हो गया है इस देश की नैतिकता, समझ और कर्तव्यबोध को? क्या हत्या का अपराध सिर्फ चौराहे पर गोली मारने को कहा जाना चाहिए? कम से कम दस साल पढ़ाई और हाउसजॉब के बाद किसी डॉक्टर से यह अपेक्षा तो की ही जा सकती है कि वह हमारी-आपकी टैक्स के रूप में वसूली गई रकम के लाखों रुपये खर्च करने के बाद इतना ज्ञानी या जिम्मेदार तो हो ही कि जिंदा और मरे में अंतर कर सके?

मोदी सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ओडिशा एम्स में डॉक्टरों को संबोधित करते हुए जुलाई, 2014 में बताया था कि एक डॉक्टर बनाने में सरकार जनता के टैक्स का आठ से दस करोड़ रुपया खर्च करती है। आखिर इनमें से चंद डॉक्टर (सभी नहीं) इतने अनैतिक क्यों हो जाते हैं कि अस्पताल और अपना बिल बढ़ाने के लिए मरे व्यक्ति को कई दिन तक वेंटीलेटर पर रख कर 'धंधा' करते हैं? क्या यह संगठित अपराध की परिभाषा में नहीं आना चाहिए? जेब काटने वाले को तो हर कोई पकड़े जाने पर दो हाथ लगा देता है और कानून भी मुस्तैद हो जाता है, पर इन पढ़े-लिखे लोगों के नाम पर चल रहे 'क्राइम सिंडिकेट' का मसला तभी क्यों सामने आता है जब मंत्री जी को मीडिया के जरिये बताया जाता है? इस पर भी गौर करें कि अधिकांश अस्पतालों में दवा एमआरपी पर ही मिलती है। पेटेंट की जगह जेनेरिक दवा लिखवाने के सारे सरकारी प्रयास विफल हो रहे हैं। कई डॉक्टर अभी भी महंगी दवा लिखकर कंपनियों से मोटी रकम कमीशन के रूप में वसूल रहे हैं। क्या कभी किसी सरकार ने पूछा है कि पांच सितारा होटलों में दवा कंपनियों के खर्चे से होने वाले मेडिकल सेमिनार कैसे चिकित्सा-ज्ञान बढ़ाने का सबब बनते हैं? इस तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। अगर आप बिहार में पैदा हुए हैं तो वहां की सरकार आपके स्वास्थ्य पर मात्र 338 रुपये खर्च करेगी, जबकि हिमाचल, उत्तराखंड या केरल में पैदा हुए हैं तो क्रमशः इसके छह गुना, पांच गुना और चार गुना खर्च करेगी। दूसरे शब्दों में उपयुक्त सरकारी सुविधा के अभाव में आप बिहार, उत्तर प्रदेश या झारखंड में गरीब होते हुए भी अपनी जेब से इसका पांच गुना खर्च करेंगे भले ही इसके लिए आपको घर या जमीन बेचनी पड़े। गुजरात और महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च क्रमशः 1040 और 763 रुपये है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत मलेरिया पर काबू पाने में असफल रहा है और आज 70 साल बाद भी केवल आठ प्रतिशत मलेरिया के मामले ही सर्विलांस के जरिये संज्ञान में आते हैं। इस मामले में भारत नाइजीरिया के समकक्ष खड़ा है। बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर और जन्म के समय बच्चे के वजन या कुपोषण आदि पैमाने पर भी भारत आज बेहद पीछे है। इसका कारण यह है कि जहां हम देश के सकल घरेलू उत्पाद का मात्र एक प्रतिशत से भी कम स्वास्थ्य मद में खर्च करते हैं वहीं चीन और कुछ छोटे-छोटे देश चार प्रतिशत तक खर्च करते हैं। हालांकि मोदी सरकार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने संसद में नई स्वास्थ्य नीति रखते हुए इसे जीडीपी का 2.5 प्रतिशत तक लाने का संकल्प जताया था, लेकिन जब बजट आया तो वह कहीं भी परिलक्षित नहीं हुआ। तो गरीब क्या करे? सरकारी अस्पताल में दवा नहीं, डॉक्टर नहीं, इलाज के उपकरण नहीं और कभी-कभी तो मंशा भी नहीं। उधर ऐसे निजी अस्पतालों की गिनती करना कठिन हो रहा है जो इलाज के बहाने धंधा कर रहे हैं। क्या कानून बनाकर अनैतिक व्यापार करने वालों पर अंकुश लगाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

परहित

जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए प्रत्येक मनुष्य अपने अंदर गुणों के विकास का प्रयास करता है। धन अर्जित कर वह सुख सुविधाएं जुटाता है। ज्ञान और बल से सम्मान पाता है। जप, पुण्य और दान से वह परलोक संवारने का भी प्रयास करता है। गुणों, उपलब्धियों से ही मनुष्य की पहचान बनती है। संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं, जिन्होंने जान पर खेलकर भी आश्चर्यजनक कार्य किए ताकि विश्व रिकॉर्ड बना सकें। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर अतिशय शिष्ट व विनम्र हो जाता है। वीरता प्रदर्शन से भी पीछे नहीं हटता। यह स्वाभाविक है, किंतु वास्तविक धर्म नहीं। मनुष्य के गुण, क्षमताएं तभी सार्थक होती हैं, जब औरों के काम आए। सदा उन्हीं को याद किया जाता है, जो परहित को समर्पित रहे। नन्हा सा दीपक भी जब जलता है तो उसका प्रकाश दूर-दूर तक फैलता है। सूर्य स्वयं में प्रकाशमान है, किंतु उसके प्रकाश से असंख्य लोगों को मार्ग दिखाई देता है। सूर्य की पूजा इस बात के लिए होती है कि वह ऊर्जा बांट रहा है।

महापुरुष इसलिए महापुरुष बने, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान से समाज को लाभान्वित किया। यदि उनका ज्ञान अपने तक ही सीमित रह जाता तो भले वे सिद्धि प्राप्त कर जाते, किंतु स्मरणीय न होते। हीरा तभी हीरा है, जब लोग उसे देखें और उसके रूप पर मोहित हों। कोई रत्न यदि गर्भ में है और लोगों की दृष्टि से ओझल है तो उसका कोई मोल नहीं। मनुष्य के ज्ञान और योग्यता का मोल भी गर्भ से बाहर निकल कर ही होता है। गुण और ज्ञान सदजीवी और सदचेतन होते हैं। यदि मनुष्य अपने हित के लिए शिष्ट और ज्ञानी बन जाए और अन्य के हित के लिए विपरीत व्यवहार करे अथवा मौन धारण कर ले तो गुणी नहीं है। उसकी स्वार्थपरता है, सरोवर के किनारे बैठे हुए बगुले और हंस एक जैसे ही लगते हैं। उनकी पहचान तभी होती है, जब बगुला कुछ भी मुंह में धारण कर लेता है, जबकि हंस केवल मोती ही चुगता है। सच्चे गुणी और ज्ञानी मनुष्य के लिए मोती परहित है। उसके लिए परहित स्वहित से आगे होता है। महापुरुष वे कहलाए, जिन्होंने अनेक कष्ट सहकर, सर्वस्व त्याग कर भी मानव समाज के हितों की रक्षा की और लोगों का सही मार्गदर्शन किया।

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

चुनावी स्वांग या प्रायश्चित कर्म

राहुल गांधी का मंदिर अभियान शीर्षक से लिखे अपने लेख में ए सूर्यप्रकाश ने राहुल गांधी के इस 'चुनावी स्वांग' के प्रति यह उचित ही शंका व्यक्त की है कि उनका यह 'मंदिर-प्रेम' कहीं अपने परनाना नेहरू के हिंदू विरोधी कृत्यों के लिए किया जाने वाला 'प्रायश्चित कर्म' तो नहीं है? यदि ऐसा है तो इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि नियति ने बाबरी ढांचा ध्वंस के पश्चात राम मंदिर निर्माण और उसके बाद में रामसेतु विवाद के समय नेहरूवादी कांग्रेस को अपनी छद्म सेक्युलर छवि से बाहर निकल कर इस देश की आध्यात्मिक चेतना से एकाकार होने का सुअवसर दिया था, लेकिन उस समय सत्तामोह में लिप्त कांग्रेस ने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को अपना राजनीतिक अस्त्र बनाकर वामपंथी मित्रों के सहयोग से इस देश की गरिमामयी संस्कृति और इतिहास के साथ खिलवाड़ करके हिंदू मानबिंदुओं का मान-मर्दन करने में ही अपनी भलाई समझी। भारत की सांस्कृतिक चेतना में समाहित राम और कृष्ण को काल्पनिक पात्र बताकर निर्दयी औरंगजेब को 'जिंदा पीर' घोषित कर देना इसका एक उदाहरण है। ऐसे में अब कांग्रेस के सरताज राहुल गांधी का पवित्र सोमनाथ मंदिर में जाना उनका 'चुनावी स्वांग' माना जाए या उस अपराध का 'प्रायश्चित कर्म' जो उनके पूर्वज नेहरू द्वारा अपनी छद्म सेक्युलर छवि बचाने के फेर में सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का विरोध करके किया गया था।

डॉ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

श्रीराम मंदिर का निर्माण

श्रीराम मंदिर निर्माण का मुद्दा जहां से शुरू हुआ था वहीं पर लटका नजर आता है। सभी इस बात को जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों? अगर हम अपने धार्मिक स्थलों का निर्माण नहीं कर सकते तो कैसा लोकतंत्र और कैसी धर्मनिरपेक्षता? कुछ वरिष्ठ पूर्व मंत्री भी इस अहम निर्णय को जल्दी आने देने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने जनता को बस वोट बैंक समझा हुआ है इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता, बस रुपये ही इनका धर्म होता है। आज दशकों बीत जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या जन्म भूमि पर त्वरित सुनवाई एक सराहनीय कदम है। सभी को जनता की धार्मिक भावनाओं और न्यायालय की कार्यवाही का सम्मान करना चाहिए।

आचार्य रामकुमार बघेल, पलवल

बेरोजगार युवा

यूपी निकाय चुनाव में भाजपा की भारी जीत मोदी लहर का नतीजा है जिसका प्रभाव गुजरात चुनाव में भी दिख सकता है। डिजिटल लेनदेन और जीएसटी आदि से राष्ट्रीय कोष को तेजी से भरने में मोदी सरकार सबसे आगे है, मगर रोजगार देने के मामले में खास प्रगति नहीं है। रेलवे समेत कई विभागों में न जाने कितने पद खाली पड़े हैं। उनकों भरने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। दिल्ली में युवा शिक्षकों की घोर उपेक्षा कर उनके स्थान पर सेवा निवृत शिक्षकों को ही लगाया जा रहा है, जबकि बेरोजगारी में युवा उम्र पार कर रहे हैं। यह सभी के साथ घोर अन्याय है।

वेद मामूरपुर, नरेला

वायु प्रदूषण

दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर श्रीलंका और भारत के बीच खेले जा रहे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत के लिए एक शर्मनाक घटना घटित हुई। मैच के दौरान फील्डिंग कर रहे श्रीलंका के खिलाड़ियों ने अपने चेहरे पर मास्क पहन लिए। ये खिलाड़ी यह दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत की आबोहवा इतनी जहरीली और प्रदूषित हो चुकी है कि यहां आकर खेलना सेहत से खिलवाड़ है। वायुप्रदूषण से संबंधित विदेश की तरफ से यह पहली प्रमुख चेतावनी है। हमें सतर्क हो जाना चाहिए।

सतप्रकाश सनोठिया, दिल्ली

नहीं सुलट रहा अयोध्या विवाद

रामजन्मभूमि अयोध्या का मुद्दा राजनीति की भेंट चढ़ने के कारण हल नहीं हो पा रहा है। इसमें सिर्फ राजनीति की जा रही है। कोई नहीं चाह रहा है कि मामला जल्द सुलट जाए। पिछले सात साल से यह केस सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन पड़ा है। अब जब जल्द सुनवाई की बात हुई तो उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश की गई। मामले को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। अभी सिर्फ दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं जिससे कि कुछ हल निकले, लेकिन हल तो तभी निकलेगा जब मामले की निरंतर सुनवाई होती रहे। इस मामले में एक पक्ष के लोग नहीं चाह रहे हैं कि इसकी सुनवाई हो, इसीलिए इनके अधिवक्ता मामले को जुलाई 2019 के बाद सुनवाई के लिए दबाव बना रहे हैं। वे अधिवक्ता कम कांग्रेस नेता के रूप में ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी नजर मुस्लिम वोटों पर भी है कि कहीं ये कांग्रेस से कट न जाएं। इसी वजह से आम चुनाव का बहाना बना रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस का शुरू से इतिहास रहा है इस तरह की राजनीति करने का। बड़ी अजीब बात है कि आज हमको रामजन्मभूमि के लिए सफाई देनी पड़ रही है, जबकि करोड़ों लोग जानते हैं कि श्रीराम की जन्म भूमि अयोध्या ही है। इसका पूरा इतिहास जन-जन के मन-मष्तिष्क में है। तमाम किताबों में भी लिखा है फिर भी बताना पड़ रहा है। आज देश में राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि लोग वोट लेने के चक्कर में अपना सब कुछ दांव पर लगा दे रहे हैं। अब चाहे वह अपनी जाति हो या धर्म या फिर अपनी नैतिकता, लेकिन एक बात तो साफ हो गया है कि दूसरा पक्ष बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इस मसले की सुनवाई हो, इसी कारण तमाम बहाने बनाए जा रहे हैं, जिससे कि यह मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सारे बहाने दरकिनार कर सुनवाई की तारीख तय कर दी है, जो शुभ संकेत है।

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

ट्वीट-ट्वीट

सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य हाजी महबूब के मुताबिक बोर्ड अपने वकील कपिल सिब्बल की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि राम मंदिर मामले की सुनवाई 2019 चुनाव के बाद हो, तो फिर सिब्बल किसके कहने पर अदालत में सुनवाई टलवाने गए थे?

सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

कर्ज लेने वालों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आरबीआइ ने ब्याज दरों में कोई कटौती ही नहीं की।

अमन शर्मा@AmanKayamHai_ET

सऊदी अरब ने रोबोट सोफिया को नागरिकता प्रदान की है। सोफिया के पास अब सऊदी महिलाओं से अधिक अधिकार और आजादी होगी। वह बिना बुर्के के भी घूम सकती है।

तसलीमा नसरीन@taslimanasreen

मैं हैरान हूं कि अरुण जेटली ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं कि जब चुनाव में असली हिंदू पार्टी मौजूद है तो नकली को क्यों वोट दें। क्या यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं। कांग्रेस इस मुद्दे पर शांत नहीं बैठेगी।

शशि थरूर@ShashiTharoor

शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा कहने से जिंदगी आसान हो जाएगी।

गीता फोगाट@geeta_phogat

जनपथ

प्यारे राहुल जी रहे मंदिर-मंदिर टेर,
सिब्बल साहब ने दिया सब पर पानी फेर।
सब पर पानी फेर अदालत में दे अर्जी,
सबको दिया बताय भक्ति है इनकी फर्जी।
अगर सिपहसालार रहेंगे ऐसे न्यारे,
फिर तो सत्ता आप पा चुके राहुल प्यारे!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, **E-mail: delhi@nda.jagran.com,** R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।